(c) It has been stated in the representation that newspaper industry is being made to pay for the inefficiencies of Public/Joint sector newsprint mills. They have also stated that 67% of the news-print requirement has to be met from the Public/Joint sector newsprint mills.

(d) Yes, Sir.

(e) The suggestions given by them have been considered as a part of pre-budget exercise of examination of representations received from various chambers of trade and industry. Action, if any, on these suggestions is reflected in the proposals for the 1994-95 budget.

Undue protection to indigenous Newsprint-Manufacturers

858. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Indian Newspaper Society has submitted a Pre-Budget Memorandum;

(b) if so, whether the Society has protested that the indigenous newsprint manufacturers are being given undue protection under the Newsprint Control Order, 1962;

(c) whether it is a fact that the prices of the indigenous newsprint has been rising; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) In terms of the Wholesale Price Index (WPI), there is practically no change in the prices of newsprint since July, 1991.

(d) The suggesstions made by a society or associations and individuals are examined by the concerned Ministries/ Departments of the Government and these suggestions are kept in view while formulating Governments's economic policies.

Buy-Back Scheme of U.T.I.

859. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Unit Trust of India has decided to buy-back the units under its various listed schemes from the market whenever such units are quoted at 10 per cent or more discount to their net asset value;

(b) details of units that are being quoted at 10 per cent or more below their net asset value; and

(c) details of the scheme that the Ministry may have approved in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Yes, Sir. The Unit Trust of India (UTI) has decided to buy-back units of its listed schemes from the market, which are quoted at least 10 per cent below their Net Asset Values (NAVs) to help market prices of units rise closer to their NAVs. The buy-back is limited to 25 per cent of the unit capital issued under any scheme in any one financial year.

(b) Details regarding units of listed schemes which are being quoted at 10 per

cent or more below their NAVs are furnished below:

Schemes	Market NAV on Discount Price at 9.2.94 % Bombay on 17.2.1994		
1. Unit Growth Scheme-2000	31.00	38.96	20.43
2. Unit Growth Scheme-5000	25.50	31.37	18.71
3. Mastershare	27.50	36.58	24.82
4. Mastergrowth	14.00	19.97	29.89
5. Mastergain	12.35	17.70	30.23
6. Masterplus	18.00	26.69	32.56

(c) The decision to buy-back the units has been taken by the Executive Committee of UTI. The decisions regarding schemes are taken independently by UTI and the Government does not take or intervene in such decisions.

बिहार के आर्थिक ढांचे में सुधार करना

860. **श्री एस०एस० अहलुवालिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय बिहार का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है और राज्य ओवर ड्राफ्ट के भंवर में फंसा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार एक मद के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि को दूसरी मदों पर खर्च कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार बिहार के आर्थिक ढांचे में सुधार करने हेतु क्या उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) अन्य कई राज्यों की तरह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार राज्य भी पांच अवसरों पर ओवरड्राफ्ट में रहा था। इन पांच अवसरों में से दो अवसरों पर राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक में अपने ओवरड्राफ्ट को अपने आप ही क्लीयर कर लिया था और बाकी के तीन अवसरों पर ओवरड्राफ्ट को केन्द्र द्वारा अगले माह की निधियों की हकदारियों को अग्रिम रूप में देकर क्लीयर किया गया था।

(ग) से (ङ) यह उल्लेखनीय है कि विकास के लिए निधियों को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में प्रवर्तित करने तथा बिहार राज्य के आर्थिक ढांचे में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचना का संबंध बिहार सरकार से है। केन्द्र सरकार अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार के परामर्श से बिहार राज्य के आर्थिक ढांचे में सुधार करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है।

बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार रोकने हेतु एक अलग प्रभाग

861. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार रोकने हेतु एक अलग प्रभाग स्थापित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस प्रभाग की स्थापना हेतु क्या प्रयास किये हैं; और

(घ) बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार की क्या संभावनाएं हैं और उक्त प्रभाग भ्रष्टाचार पर किस प्रकार नियंत्रण रखेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बैंक ऋणों का दुरुपयोग

862. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में बैंक ऋणों के दुरुपयोग संबंधी जानकारी नहीं रखी जाती है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंक ऋणों का दुरुपयोग बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो बैंक ऋणों का दुरुपयोग रोकने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (घ) बैंक अपने ऋण मामलों के रिकार्ड रखते हैं तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में ऋण वसूली के लिए